(ii) The major components of the Project are:

- Setting up and strengthening of 14 Agro-Based Vocational Training Centres in the State.
- Capacity Building and Skill Upgradation of farm women through various types of training such as village level training, institutional training etc.
- Extension Support to farm women through Result Demonstrations, Study Tours, Mahila Goshtis & Organisation of Charcha Mandals.
- Infrastructural & Administrative Support through civil works, equipment, staff and mobility.
- Monitoring & Evaluation Support.
- Setting up of Mobile Marketing Unit.

(iii) The Government of Kerala has forwarded the aforesaid project for availing Dutch Assistance. The Dutch Authorities have, however, expressed their inability to commit themselves to new projects, including the proposed project in Kerala, due to drastic cuts in their budget.

मालपा त्रासदी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

272. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या प्रधान मंत्री 3 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 469 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष उतरांचल के ऊखीमठ तथा मालपा में भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा क्या सीधी राहत उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या ऊखीमठ क्षेत्र में कालीमठ-मनसूना इलाकों के एक दर्जन से भी अधिक गांवों को हटाये जाने का प्रस्ताव है और क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के साथ कोई चर्चा की है;

(ग) इन गांवों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जायेगा तथा उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन्हें पुन: बसाया जायेगा; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अधिकारियों का दल भेजा था; यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) राज्य सरकार को आपदा राहत कोष में केन्द्र सरकार अपने 75 प्रतिशत हिस्से का अंशदान करती है तथा प्रभावित लोगों में वास्तविक सहायता का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य को वर्ष 1998-99 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की 52.035 करोड़ रु० की तीसरी तथा चौथी त्रैमासिक किस्तें अगस्त, 1998 में अग्रिम तौर पर निर्मुक्त कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत व पुनर्वास उपायों के लिये 137.10 लाख रु० निर्मुक्त किये जाने की जानकारी मिली है जिसमें से 116.525 लाख रु० मालपा दुर्घटना के संबंध में राहत व पुनर्वास उपायों पर व्यय किये जाने की सूचना है।

(ख) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव इस संबंध में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) भू-स्खलनों के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिये एक अन्त: मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

Air Journey on LTC

*273. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow air journey for all India LTC to areas like North-Eastern region, Andaman and Nicobar Islands, Lakshdweep, etc. as recommended by the Fifth Pay Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and by when Government propose to do it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (c) The Government has not accepted the recommendation of the Fifth Central Pay Commission regarding